

राहुल गांधी को भारी दुविधा में डाला महिला आरक्षण विधेयक ने

राहुल गांधी विधेयक में ओबीसी कोटा यानी कोटे में कोटा के लिए संघर्ष कर रहे थे

- रेणु मिश्रा -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 11 अप्रैल। महिलाओं के आरक्षण बिल को दो-तिहाई बहुमत से पास कराने के लिए सरकार को 364 मतों की आवश्यकता है, जो बिना विपक्ष के सक्रिय सहयोग, समर्थन और मतदान के हासिल करना थोड़ा कठिन है।

विपक्षी दल राहुल गांधी पर इस बात का बहुत दबाव डाल रहे हैं कि वे महिलाओं के आरक्षण बिल में (अन्य पिछड़ा वर्ग) मुद्दे को मजबूत ढंग से उठाएँ। इस "कोटा के भीतर कोटा" ने सरकार की स्थिति को कठिन बना दिया है।

विपक्षी नेता यह भी ज़िद कर रहे हैं कि राहुल गांधी ओबीसी मुद्दे को पूरे देश स्तर पर उठाएँ।

समस्या यह है कि अपनी करीबी "जय जगत" टीम के प्रभाव में, राहुल गांधी ने ओबीसी मुद्दे को किनारे कर

पर, राहुल की "किचन कैबिनेट" जय जगत का मत है, राहुल को विधेयक में ओबीसी कोटा की मांग नहीं उठानी चाहिए, बल्कि विधेयक में दलित कोटा डालने की मांग पर अड़ना चाहिए।

ऐसी दुविधा राहुल गांधी के समक्ष बिहार चुनाव अभियान के दौरान भी आई थी इसलिए वहाँ चुनाव अभियान के दौरान वे अचानक ही ओबीसी की बात त्याग कर दलित उत्थान की बात करने लगे थे।

अब अगर राहुल ओबीसी कोटा की बात करते हैं, जैसा कि संपूर्ण विपक्ष चाहता है या तो जय जगत ग्रुप नाखुश होता है और अगर दलित उत्थान की बात करते हैं तो जय जगत ग्रुप खुश होता है, पर, विपक्ष निराश होता है।

और अगर ओबीसी कोटा की बात करते-करते अचानक दलित उत्थान की ही बात करते हैं तो वर्तमान राजनीति परिस्थिति में यह उचित नहीं लगता और वे अचानक दलित उत्थान की बात छोड़कर ओबीसी कोटा पर जोर देने लगते हैं, तो यह छवि बनती है कि शायद राहुल ओबीसी व दलित के फर्क से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। यह भी राहुल की छवि के लिए ठीक नहीं है।

दिया है, वास्तव में उन्होंने इसे तो छोड़ दिया और दलित मुद्दे को उठा लिया। यह

बिहार चुनाव के दौरान भी दिखा, जब राहुल ने अचानक अपनी रणनीति बदल दी थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान मान भी जाए तो भी नहीं खुल पाएगा होर्मुज़ स्ट्रेट!

असल में ईरान ने युद्ध के दौरान होर्मुज़ स्ट्रेट में कई "नेवल माइन्स" बिछाई थीं, पर उसे खुद याद नहीं कि ये माइन्स किस जगह पर हैं

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 11 अप्रैल। भले ही ईरान अमेरिकी शर्तों के अनुसार व्यावसायिक जहाजों को होर्मुज़ (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़) से स्वतंत्र और निर्बाध रूप से गुजरने की अनुमति देने के लिए तैयार हो जाए, ताकि संघर्ष को औपचारिक रूप से समाप्त किया जा सके, फिर भी तेहरान के सामने एक अस्थायी कठिनाई है। जाहिर तौर पर, ईरान भूल गया है कि उसने स्ट्रेट में कितनी नेवल माइन्स बनाने की योजना बनाई थी, या वे कहाँ हैं। अमेरिकी रिपोर्टों के अनुसार, नौसैनिक खानों को ईरान ने न तो तेज़ और न ही कुशल तरीके से बिछाया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के पास बिछाई गई खानों की संख्या और स्थान का सटीक रिकॉर्ड नहीं हो सकता। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के

न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसने किस-किस जगह पर "माइन्स" बिछाई थीं, यही नहीं समुद्री लहरों से माइन्स के जगह बदलने का भी खतरा है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने से पहले कई तकनीकी सीमाओं पर विचार करना होगा। अमेरिकी विशेषज्ञ इसे "माइन्स" बिछाने की स्वीकारोक्ति मान रहे हैं।

हवाले से कहा गया है कि जल-धाराओं के कारण उनमें से कुछ खानों का मूल स्थान भी बदल जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। खाने बेतरतीब तरीके से बिछाई गई थीं, जिससे व्यवस्थित रूप से उन्हें हटाना अत्यंत कठिन हो गया।

स्ट्रेट को जल्दी ही नहीं खुलवा पाने का स्पष्ट रूप से कूटनीतिक असर

होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अस्थायी युद्धविराम की संभावना को जलमार्ग को पूर्ण, तात्कालिक और सुरक्षित खोलने से जोड़ा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अप्रत्यक्ष रूप से इस समस्या को स्वीकार करते हुए कहा है कि स्ट्रेट का पुनः खुलना तकनीकी सीमाओं के

खेड़ा को मिली एक सप्ताह की ट्रांज़िट अग्रिम जमानत

- जाल खंबाता -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 11 अप्रैल। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा को असम पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के संबंध

तेलंगाना हाई कोर्ट ने असम पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के खेड़ा के भय को स्वीकार किया और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत सीमित सुरक्षा प्रदान की। अब खेड़ा को 7 दिन में असम की किसी कोर्ट से जमानत लेनी होगी।

में एक सप्ताह की ट्रांज़िट अग्रिम जमानत दी। यह एफआईआर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोने के खनन को लेकर चिंता जताई थरूर ने

- जाल खंबाता -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 11 अप्रैल। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है कि भारत ऐसा देश है, जहाँ स्वर्ण धातु के लिए भारी जुनून है। हम अनुमानित 500 मिलियन टन सोने के अयस्क भंडार पर बैठे हैं, लेकिन हमारा थरू उद्योग वैश्विक रजिस्टर में न्यूनतम है, हम सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में सोना निकालते हैं, सालाना लगभग डेढ़ टन, जबकि ऑस्ट्रेलिया, घाना और पेरू की खानों से सैकड़ों टन सोना निकालने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को खर्च करते

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हमारे पास स्वर्ण अयस्क (गोल्ड और) के 500 मिलियन टन भंडार हैं, पर, हम साल में सिर्फ डेढ़ टन सोना ही निकालते हैं।

है। यह स्थिति सिर्फ विडंबना नहीं है, यह एक आत्म प्रहार है, जो हमारी आर्थिक संप्रभुता को कमजोर करता है, जबकि विश्व व्यवस्था टूट रही है।

उन्होंने आगे कहा, "एक संभावित खननकर्ता को जो नियामक भूलभुलैया पर करनी पड़ती है, वह इतनी जटिल और प्राचीन है कि यह वास्तव में अडचन की तरह काम करती है।

थरूर ने यह भी बताया कि जहाँ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका-ईरान वार्ता शुरू हुई, पर शुरुआत काफी ढुलमूल सी है

वार्ता बीच में ही टूटने के आसार हैं, अतः मामूली सी सफलता का बड़े जोर-शोर से स्वागत हो रहा है

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 11 अप्रैल। ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता शुरू हो गई, सभी आशंकाओं के बावजूद, हालांकि शुरुआत अस्थिर रही। विफलता के डर के कारण, हर छोटी प्रगति को भी खास तौर पर महत्व दिया जा रहा है।

बहुत कम उम्मीदों के साथ, यह वार्ता कुछ ठोस परिणाम भी दे सकती है। कूटनीतिक सौदेबाजी के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान का पलड़ा भारी है और वह अपेक्षित से अधिक लाभ कमा रहा है।

होर्मुज़ स्ट्रेट के तुरंत पुनः खोलने के मुद्दे को टालते हुए, ईरान अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को वार्ता शुरू होने से पहले उजागर कर रहा है। भारी आर्थिक दबाव में, ईरान ने अमेरिका से वार्ता की शुरुआत में ही एक बड़ी रियायत हासिल कर ली है।

ईरानी प्रतिनिधिमंडल के नेता मोहम्मद बगर गलीबाफ ने मांग की कि अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत विभिन्न ईरानी संस्थाओं के भारी वित्तीय संसाधन जब्त किए गए हैं। जब्त की गई ईरानी धनराशि को वार्ता शुरू होने से

■ अभी तक तो यह ही छवि बनी है कि ईरान हावी है तथा ट्रंप किसी भी तरह वार्ता जारी रखना चाहते हैं।

■ इस माहौल में ईरान ने प्रारंभ में अपनी बात मनवा ली कि "फ्रीज़" खातों से पैसे रिलीज़ होंगे, अमेरिका 6 बिलियन डॉलर कतर बैंक से रिलीज़ कराने को तैयार है।

■ ईरान के दबाव में अमेरिका ने इज़रायल को लेबनान पर फिलहाल बमबारी रोकने की सलाह/आदेश दिए हैं तथा बमबारी काफी कम हो गई है।

■ इस भगदड़ के माहौल में होर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाने की बात भी गौण सी हो गई है। ट्रंप की मजबूरी यह है कि अमेरिका में कीमते एक प्रतिशत बढ़ गई हैं तथा महंगाई 3.3 प्रतिशत बढ़ी है।

पहले ही जारी किया जाना चाहिए।

हालांकि अमेरिका लगातार यह कह रहा है कि अगर वार्ता विफल होती है तो इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव होगा, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ट्रंप युद्ध से स्थायी निकासी के लिए समाधान खोजने के लिए बेताब है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका ने वार्ता

शुरू होने से पहले ही कतर के बैंक में रखी 6 बिलियन डॉलर की राशि जारी करने पर सहमत दे दी है।

ईरान ने यह भी कहा कि लेबनान पर हमला करना और वार्ता को जारी रखना एक साथ नहीं हो सकता। वार्ता शुरू होने से पहले लेबनान में ईरान के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी ने राहुल से बात की, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

सूत्रों ने बताया कि प्र.मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उनकी माँ सोनिया गांधी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा

- डॉ. सतीश मिश्रा -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 11 अप्रैल। संसद में दिन के उजाले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच हुई छोटी और सौहार्दपूर्ण बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ चर्चा का विषय बन गया।

दो नेताओं के बीच यह संवाद - जो वर्तमान भारत की घुचीकृत राजनीति में दुर्लभ है - पुरानी यादों को ताजा कर देता है, जब सत्ताधारी दल और विपक्ष राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हुआ करते थे, शत्रु नहीं।

हालांकि बातचीत को सामग्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने गांधी से उनकी माता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा, जिन्हें हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

■ सूत्रों ने बताया कि राहुल ने कहा कि अब उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है तो प्रधानमंत्री ने संतोष जताया और शुभकामनाएं दीं।

■ यह मौका था ज्योतिराव फुले की जयंती के अवसर पर संसद परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि देने का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक साथ थे।

■ सोशल मीडिया पर इस वीडियो की काफी चर्चा हुई! यूजर्स ने इसे वर्तमान राजनीतिक वैमनस्य के माहौल में दुर्लभ क्षण बताया।

एक सूत्र ने कहा, गांधी ने उन्हें बताया कि उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है।

जवाब में प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया और शुभकामनाएं दीं।

सोनिया गांधी को 31 मार्च को सिस्टीमिक इंफेक्शन से ठीक होने के बाद सर गंगा राम अस्पताल से छुटी दे

दी गई थी। उन्हें 24 मार्च को बुखार के कारण भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री और कांग्रेस सांसद उन नेताओं में शामिल थे, जो शनिवार को संसद परिसर में समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए थे।

शनिवार सुबह पर प्रधानमंत्री मोदी ने फुले को "मार्गदर्शक प्रकाश" कहा और लिखा कि शिक्षा, सीख और सबके कल्याण पर उनका जोर आज के समय में भी प्रासंगिक है।

उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री ने लिखा, संसद परिसर में महात्मा फुले को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके आदर्श अनगिनत लोगों को शक्ति और आशा देते रहे।

दृश्यों में दोनों नेताओं को पास-पास खड़े दिखाया गया, जो एक छोटी लेकिन एकाग्र बातचीत में व्यस्त थे, उसके बाद उन्होंने अपने-अपने कार्यक्रम जारी रखे। भले ही यह बातचीत क्षणिक थी, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच लगातार होने वाले राजनीतिक झगड़ों के बीच यह अलग नज़र आई। यह दृश्य देखने वाले पर्यवेक्षकों ने इस आदान-प्रदान पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आशा भोंसले को हार्ट अटैक

मुंबई, 11 अप्रैल। दिग्गज सिंगर आशा भोंसले को शनिवार, 11 अप्रैल को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैन्डी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। सूत्रों के अनुसार, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

आशा भोंसले की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में फिलहाल कोई और जानकारी

■ ब्रीच कैन्डी अस्पताल में भर्ती, हालत अभी गंभीर

उपलब्ध नहीं है। उनके परिवार और अस्पताल अधिकारियों ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। आशा भोंसले की पोती जनाई भोंसले ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए हेल्थ अपडेट साझा किया है। उन्होंने बताया कि 'अत्यधिक थकावट और सोने में संक्रमण के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जनाई भोंसले ने अपनी पोस्ट में आशा भोंसले को दिल का दौरा पड़ने वाली बात नहीं बताई है।

'हमारे इरादे नेक हैं, पर, हमारा अमेरिका में विश्वास डगमगा रहा है'

ईरान के प्रतिनिधिमंडल के मुखिया मोहम्मद बकर गलीबाफ ने वार्ता शुरू होने से पहले यह भी कहा, "अमेरिका से बातचीत का सिलसिला "फेलियर" व टूटे हुए वादों से अटा हुआ है

- डॉ. सतीश मिश्रा -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 11 अप्रैल। 40 दिनों तक चले विनाशकारी युद्ध के बाद अमेरिका-इज़रायल और ईरान के बीच युद्धविराम को समाप्त करने और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौते तक पहुँचने के लिए शांति वार्ता आज इस्लामाबाद में औपचारिक रूप से शुरू हुई। इस संदर्भ में, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज़ खुलेगा और जल्दी ही खुलेगा।

अपनी शेखी बघारने वाले कूटनीतिक रवैये के माध्यम से, ट्रंप ने ईरान को विफलता की ओर बढ़ता राष्ट्र कहा और यह स्पष्ट किया कि यदि वार्ता योजना के अनुसार नहीं हुई तो अमेरिका

फिर से हमले करने के लिए तैयार है। पश्चिम एशिया में नए संघर्ष को रोकने के प्रयास ने 11 अप्रैल को गति पकड़ी। जब अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडल दो सप्ताह के अस्थिर युद्धविराम के दौरान उच्च-स्तरीय वार्ता के लिए इस्लामाबाद में मिले।

लेकिन पहले औपचारिक सत्र से पहले ही वार्ता का माहौल तनावपूर्ण रहा, घमकियों, अविश्वास और सार्वजनिक वाद-विवाद जारी रहे, जिसमें ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने पोस्ट के माध्यम से आक्रामक स्वर से काम लिया।

अब ध्यान होर्मुज़ स्ट्रेट पर केन्द्रित हो गया है, जो अब सैन्य और कूटनीतिक दबाव का केन्द्र बन गया है। जहाँ

■ ट्रंप ने बातचीत के दौर की शुरुआत अपनी छाती ठोकते हुए, बडबोलेपन से की और कहा, "ईरान एक फेल्ट राष्ट्र है" और अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो वे दोबारा लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार हैं।

■ ट्रंप ने यह भी दंभ भरा कि उसके पास सबसे बड़े ऑयल प्रॉड्यूसिंग देश के पास जितना ऑयल है, उससे ज्यादा ऑयल है और अब बड़े-बड़े ऑयल टैंकर बीच में ही अपना रास्ता बदलकर अमेरिका जा रहे हैं, टैंकरों में ऑयल भरने के लिए।

■ ट्रंप का दावा शायद सही है, पर क्या अमेरिका की ऑयल सप्लाई विश्व की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है।

वाॉशिंगटन कहता है कि जलमार्ग "ईरान के सहयोग या इसके बिना" खुल

जाएगा, वहीं तेहरान ने अमेरिका पर गहरा अविश्वास जताया और किसी भी

सार्थक प्रगति को शर्तों से जोड़ दिया, जिनमें लेबनान में युद्धविराम और फंसे हुए ईरानी संसाधनों की रिहाई शामिल है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा कि आगामी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान से होने वाली वार्ता में उनका फोकस यह सुनिश्चित करने पर होगा कि तेहरान कोई परमाणु हथियार नहीं रख सकता। उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट "ईरान के समर्थन या उसके बिना" खुला रहेगा।

वाॉशिंगटन से दौरे के लिए रवाना होने के बाद, पत्रकारों से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के साथ किसी भी स्वीकार्य समझौते से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि उसके पास